Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 04-12-2006
Participants : Mehta Shri Alok Kumar,Acharia Shri Basudeb,Suman Shri Ramji Lal,Mistry Shri Madhusudan Devram

an>

Title: Alleged improper utillization of Central fund for the rehabilitation, health and education of riot victims in Gujarat.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद):अध्यक्ष महोदय, गुजरात राज्य में वर्ा 2002 में दंगा हुआ था यह सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा था। इसमें ढाई हजार अल्पसंख्यक लोग मारे गए थे, राज्य सरकार के मुताबिक लापता लोगों की संख्या 250 है जबकि गैर-सरकारी संस्थाओं के मुताबिक यह संख्या 500 है। इसमें10,000 से ज्यादा लोग दयनीय अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं। लगभग 61,000 दंगा पीड़ित लोग घरों से विस्थापित हैं और 18,000 छोटे-छोटे गांवों से मुसलमानों ने पलायन किया है। ...(व्यवधान) गुजरात के जो पीड़ित लोग हैं, उनका पुनर्वास नहीं हुआ है ।...(व्यवधान) हम, कुछ सांसद अहमदाबाद में गए थे, वहां मौके पर जाकर हमने स्वयं देखा है कि वहां लोगों की स्थिति बहुत खराब है। हम स्वयंसेवी संगठनों को धन्यवाद देते हैं कि जिनके प्रयासों से दंगा पीड़ितों के पुनर्वास का इंतजाम हुआ है। राज्य सरकार को अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए था लेकिन राज्य सरकार ने उस धर्म का निर्वाह नहीं किया। सबसे तकलीफ की बात यह है कि भारत सरकार ने उन लोगों के पुनर्वास के लिए 150 करोड़ रुपए राज्य सरकार के पास भेजे थे, उसमें से भी 19 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने वापिस भेज दिए। यह बहुत गंभीर मामला है। राज्य सरकार संवेदन शून्य सरकार है ...(व्यवधान)और लोगों की जानमाल की रक्षा, पुनर्वास का इंतजाम, खाने, रहने, स्कूल और अस्पताल आदि की कोई भी व्यवस्था गुजरात में नहीं की गई है। [r4]

जिन अधिकारियों ने अपने धर्म का निर्वाह किया, उन्हें हतोत्साहित करने एवं दंगों में शामिल अधिकारियों को प्रोन्नत करने का काम राज्य सरकार ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, गुजरात की स्थिति बहुत गंभीर है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वहां लोगों में अभी भी भय और निराशा का वातावरण सरकार ने पैदा किया हुआ है। इसके अलावा एक आदमी जो मुसलमानों के कत्लेआम में शामिल था, दि.10.04.05 को वडोदरा में उसकी मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें स्थानीय सासंद और विधायक भी शामिल हुए थे। उसकी मूर्ति के नीचे लिखा गया कि यह हिन्दुत्व की रक्षा के लिए शहीद हो गया। गुजरात राज्य में अल्पसंख्यकों की जान-माल की सुरक्षा नहीं हो सकती। वहां की सरकार दंगा पीड़ितों के पुनर्वास का कोई इंतजाम नहीं कर पाई। इसलिए हमारी मांग है कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, जिससे लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): अध्यक्ष महोदय, सेक्युलर पार्टीज के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 30 तारीख को गुजरात के अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में बसे दंगा पीड़ितों के कैम्पों का दौरा किया। इस दौरे में मैं भी एक सदस्य था और श्री लालू प्रसाद जी ने इस दौरे के लिए मुझे भेजा था। हम लोगों ने लगभग आठ शरणार्थी कैम्पों का दौरा किया, जो विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं एवं ट्रस्टों द्वारा निर्मित और संचालित थे तथा जो अपने सीमित संसाधनों के साथ ट्रस्टों और संस्थाओं के साथ इंतजामों में लगे हुए थे। वहां चंद लोगों को पांच सौ से सात हजार रुपये अनुग्रह राशि देकर राज्य सरकार ने अपना हाथ छुड़ा लिया और जिन परिवारों के लोग मारे गये, उन्होंने पांच सौ से लेकर 6-7 हजार रुपये के चैकों की फोटो स्टेट कापियां हमें दिखाईं। वहां केवल 15 प्रतिशत लोगों को किसी न किसी रूप में सहायता मिल सकी। वहां ट्रस्टों को शिविर बनाने के लिए ऐसी जमीनें दी गईं कि जहां पूरे शहर का कचरा फेंका जाता है।प्रदूति जल का सेवन करने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। वहां माताओं के दूध सूख रहे हैं और बच्चे विक्लांग हो रहे हैं। वहां कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी वहां दहशत का वातावरण बनाया हुआ है। वहां तमाम विक्टिम्स अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वे अपने घरों को वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास की यह सबसे शर्मनाक बात है कि ढाई वर्ा के बाद भी पुनर्वास के कोई उपाय नहीं किये गये। ऐसे में केन्द्र सरकार की ओर से दंगा पीड़ितों की सहायता के लिए 150 करोड़ रुपये भेजे गये थे, उसमें से

19 करोड़ रुपये राज्य सरकार केन्द्र सरकार को वापस भेज रही है। हमारी टीम ने सत्य नगर, किफायत नगर, मुहाजिर नगर, सिटीजन नगर, सिद्दिकाबाद और सर्वाधिक दंगापीड़ित सरदारपुर का दौरा किया। वहां दंगा पीड़ितों की कहानियां सुनकर हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारी आंखों से आंसू बाहर निकल आयेंगे। अभी भी वहां पांच सौ लोग गायब हैं,जिनके बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश अभी भी नहीं हो रही है। इसलिए हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि वह इस दिशा में पहल करे और जल्द से जल्द दंगा पीड़ितों की सहायतार्थ पुनर्वास का इंतजाम करे और उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे, यही हमारी मांग है। …(व्यवधान)

MR. SPEAKER: You cannot discuss the matter concerning the State Government.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You are deliberately obstructing the business of the House. I cannot allow this.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You have not even given a notice.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, a delegation of nine Members of Parliament have visited Gujarat on Thursday, the 30th November, 2006 to see the condition and the rehabilitation of the carnage-affected people of Gujarat. … (*Interruptions*) Even after a lapse of about four years, the affected people have not yet been properly rehabilitated. … (*Interruptions*)[MSOffice5]

… (*Interruptions*) Houses of two lakh people were gutted. What we have seen is that the State Government of Gujarat has not spent a single pie for the rehabilitation of those people. Only voluntary organizations, NGOs, etc. constructed some houses. No civic amenities were being provided to these people. There are no roads, there are no schools, there are no medical facilities and there are no provisions for drinking water. They are living in very miserable and inhuman conditions.* ... today is returning whatever money was sent by the Central Government for rehabilitation. They have returned Rs.19 crore to the Central Government. They could have spent this amount of Rs.19 crore for providing drinking water facilities, sanitation facilities, for construction of schools and for providing medical facilities. I demand that the Central Government should immediately intervene.

Justice Nanawati Commission had recommended compensation for the victims of 1984 riots. I demand that a similar compensation should be paid to the victims of minority communities who were killed in this carnage. People, whose houses were damaged, received only Rs.2,000-Rs.3,000. They should be properly compensated and the Gujarat Government should be told to provide basic civic amenities to those people. I demand that the Central Government should immediately intervene so that basic civic amenities are provided. … (*Interruptions*)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान गुजरात के दंगा पीड़ितों की ओरकेन्द्रित करना चाहता हूं। जो लोग इन दंगों में मारे गये या जो लोग बेघर हुए, वैसे लोगों के लिए 150 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दिये थे लेकिन मुझे कहते हुए दुख होता है कि इनके नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के निर्वाचन क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये के अंदर गुजरात की सरकार ने 19 करोड़ दस लाख रुपये वापस लौटाए। इतना ही नहीं, जो लोग बेघर हुए थे और जो घायल हुए थे, उनको गुजरात की सरकार ने उसके पैसे में से एक भी पैसा नहीं दिया। केन्द्र के पैसे में से खर्च किये गये। इतना ही नहीं, सिर्फ 1150 लोगों को

ही यह मुआवजा दिया गया है। ...(व्यवधान) मुझे कहते हुए शर्म आती है कि इनके जो मुसलमान एमपीज हैं, उन मुसलमान एमपीज को यहां से इस्तीफा दे देना चाहिए जो गुजरात को रीहैबिलिटेशन बराबर नहीं करा सके।...(व्यवधान) गुजरात **... की सरकार सिर्फ भेदभाव कर रही है मैं जानता हूं कि लाल कृण आडवाणी जी उनको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि श्री लाल कृण आडवाणी उनकी सहायता के बिना वहां से चुनाव जीत नहीं सकते*** ... (व्यवधान) राज्य के पैसे में से कुछ भी नहीं देते।

Not recorded

मेरी मांग है कि इस रीहैबिलिटेशन को केन्द्र के स्तर तक लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुआवजा दिया जाए...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: That will be deleted. The other hon. Members who have given notices to raise this issue – Shri Hannan Mollah, Shri Devendra Prasad Yadav and Shri C.K. Chandrappan – can associate themselves.

... (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA :We want a response from the Government. ... (*Interruptions*)